

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या -235 / 2015 / जयपुर
2. अपील संख्या -236 / 2015 / जयपुर
3. अपील संख्या -237 / 2015 / जयपुर

मैसर्स लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स,
बी-20, रायसर प्लाजा, इन्दिरा बाजार, जयपुर।
बनाम्

.....अपीलार्थी.

1. अपीलीय प्राधिकारी तृतीय,
वाणिज्यिक कर, जयपुर।
2. सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ (कैम्प जयपुर)
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक।
श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12.07.2017

निर्णय

1. प्रस्तुत तीनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 18.11.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24.10.2013 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से बैटरी/एडोप्टर/मोबाईल चार्जर पर आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखे जाने को विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	क.नि.वर्ष	कर	ब्याज
235 / 15	402 / अपीलस-III / आरवीएटी	10-11	8,81,684	3,35,040
236 / 15	403 / अपीलस-III / आरवीएटी	11-12	12,06,680	3,13,737
237 / 15	404 / अपीलस-III / आरवीएटी	12-13	5,02,540	70,355

2. प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी फर्म के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 11.07.2013 को किये जाने पर पाया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में बैटरी / एडोप्टर / मोबाईल चार्जर की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से वेट वसूल किया जाकर राजकोष में जमा करवाया गया।





क्रमशः.....2

सशक्त अधिकारी द्वारा माना गया कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद बैट्री/एडोपटर/मोबाईल चार्जर अधिनियम की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं षष्ठम में अधिसूचित वस्तु नहीं होने के कारण यह अधिनियम की अनुसूची पंचम के तहत सामान्य कर दर 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में उक्त तालिका अनुसार 9 प्रतिशत की दर से अंतर कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त व्यवहारी द्वारा कराप्रवंचन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गयी। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपीलें बिक्रीत उत्पाद बैट्री/एडोपटर/मोबाईल चार्जर पर आरोपित धारा 61 की शास्ति को अपास्त किया तथा आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने बैट्री/एडोपटर/मोबाईल चार्जर पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित सामान्य कर को यथावत रखना अनुचित एवं अविधिक है। उक्त वस्तुएँ मोबाईल फोन बैट्री/मोबाईल चार्जर अधिनियम की अनुसूची चतुर्थी की प्रविष्टि संख्या 65 के पार्ट ए की प्रविष्टि संख्या 12 व 28 से आच्छादित है, जो एक मॉडल स्पेसिफिक वस्तुएँ होने के कारण अन्यथा किसी प्रकार से उपयोग नहीं किये जाने से यह वस्तुएँ मोबाईल फोन के पार्टस की श्रेणी में आती है। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि "A thing is the part of which is incomplete without thing. Any instrument not capable of delivering the message/voice is not a telephone and when batter is not put into telephone can it transmit the voice. RVAT Act provides for Cellular phones. Thus without battery a cell phone can not be called cell phone. It is not a phone at all. Does it mean that a person selling cell phone does not come under the entry of Cell Phone?"

Under RVAT Act 2003 the entries notified in the list of I.T. Products are separate to each other, therefore, they are to be read separately either it is entry no. 12 or 13 or 28. The case cited by learned CTO of Merathan India is on entry no. 13 of I.T. Products. Radio Pager Battery may be or may not be part of radio pager but mobile battery is essential part of cellular phone in entry no. 12. Entry no. 28 is with regard to parts of items mentioned in entries from 1 to 27. In other words the entry of parts is to be read separately and it is very much clear that when the part of the main item covered under entry 1 to 27 are sold the same shall be taxable at the rate of tax prescribed for by entry no. 28. It does not matter that the said part is sold along with the main item or without main item of 1 to 27. If there would have been otherwise intention of the

legislature then the Rate of tax on the parts of the mobile phones would have been notified separately under the entry no. 12 by specifically debarring the batteries, adaptors and chargers there from. Entry no. 28 is not a list for defining the goods rather it is a list to make it clear that "Parts" of the commodities from 1 to 27 are covered independently. In the judgment of Merathan India the interpretation of word "including" has been done by the Hon'ble RTB but no where in the said judgment the discussions regarding entry no. 28 has ever been made and no discussions has ever been made on the word "excluded" which is also a factor to be considered for determining the rate of tax on a commodity."

अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

1. The High Court of Jaipur Bench Jaipur S.B. Revision Petition No. 129 of 2012 M/s Marathon India Ltd Vs Commercial Taxes Department, Circle "J", Jaipur Dated 02-12-2016
2. Gujrat High Court Vikas Traders Vs The State of Gujarat Dated July 31, 1975
3. The High Court of Jaipur Bench S.B. Sales Tax Revision No. 297/2011 Assistant Commercial Tax Officer, Zone-II, Ajmer Vs M/s Swastik Agencies, Ajmer Date 16-08-2015
4. Supreme Court of India Assistant Commercial Tax Officer Zone-II, Ajmer Vs M/s Swastik agencies, Ajmer Date 28-03-2016.
5. [2014] 45 taxmann.com 111(Karnataka) High Court of Karnataka Vs Mysore Thermo Electric (p.) Ltd. March 21, 2014.
6. In the High Court of Jodhpur ACTO, Ward-I, Circle-C, Jodhpur Vs M/s Industrial Instruments, Jodhpur S.B. Civil Revision (Sales Tax) No. 331/2005 Feb. 14, 2013
7. Supreme Court of India Assistant Commercial Taxes Officer Vs M/s Industrial Instruments, Jodhpur Dated 21.01.2015
8. 1981 U.P.T.C.-974 Sales Tax Revision No. 103 of 1978 Dated 14 May 1981 Commissioner of Sales Tax Vs Banaras Battery Works
9. Madras High Court Tax Case (Revision) No. 24 of 1978 Premier Instruments Coimbatore Limited Vs State of Tamil Nadu Date September 14, 1983
10. Rajasthan Tax Board, Ajmer Appeal No. 733/2000/Ajmer Ms Kiran Battery Company Vs Asstt. comer. Taxes Officer Dated 31.01.2003
11. (2003) 2 Supreme Court Cases 371 AIR 2003 SC 986 (2003) 152 ELT 3 G.S. Auto International Ltd Vs Collector of Central Excise Chandigarh Dated 15.01.2003.
12. In the Supreme Court of India Appeal No. 11486-11487 of 2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd.
13. राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1998 से 2002/2013/जयपुर मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०, जयपुर बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 05.06.2017.
14. राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 853 से 855/2015/जयपुर मैसर्स माइक्रोमैक्स इन्फोरमेटिक्स लि०, जयपुर बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 27.06.2017.
15. राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 436 से 439/2016/अलवर मैसर्स नोकिया इण्डिया प्रा०लि०, अलवर बनाम अपीलीय प्राधिकारी अलवर निर्णय दिनांक 29.06.2017.

उन्होंने निवेदन किया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी को सामान्य कर दर से निर्धारित नहीं करते हुए अनुसूची चतुर्थ के तहत निर्धारित किया है, अतः उक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में इन प्रकरणों में भी बैटरी की कर दर होगी। उन्होंने कथन किया कि बैटरी चार्जर के बिना बैटरी/एडोपटर/मोबाईल चार्जर संचालित ही नहीं

हो सकते हैं, अतः इन पर भी माननीय राजस्थान का उपरोक्त उद्धरित निर्णय के सिद्धान्त लागू होने से 5 प्रतिशत की करदेयता लागू होगी। उन्होंने उक्त निर्णयों के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम नोकिया इण्डिया प्रा.लि. निर्णय दिनांक 17.12.2015 सिविल अपील संख्या 11486-11487 / 2014 में बैटरी चार्जर पर सामान्य कर दर निर्धारित की है।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि मोबाईल फोन के साथ विक्रय की गई बैटरी एवं एडोपटर/चार्जर पर कर देयता किस दर से निर्धारित होगी। इस संबंध में हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय एस.बी. एसटीआर पिटीशन नं० 129 / 2012 मैराथॉन इण्डिया लि० बनाम सीटीओ निर्णय दिनांक 02.12.2016 में बैटरी पर निर्णय पारित किया गया है, जिसके अनुसार बैटरी पर करदेयता 4 / 5 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय का सुसंगत विवरण निम्नानुसार है :-

".....This court in ACTO V. M/s Swastik Agencies(supra), had an occasion to consider a case where battery which was fitted into a Motor Car and this court, after taking into consideration few of the judgments, held that same rate is to be applied on sale of batteries as that of a motor Car, though there was a finding that the batteries which are to be fitted in Motor Cars can be used for other diverse purposes then too, this court came to the conclusion that a nominal sale be that as it may of such batteries could not alter the nature of the transaction, whereas in the instant case there is a specific certificate of the Army Authority that the said battery can only be used as a part/integral part of RCRs, admittedly entire sale is to the ARMY only and for specific use alone.

.....
In the case of Vikas Traders V. The State of Gujarat (supra), the court took into consideration as to whether batteries were component parts and there was a finding that batteries were being used for tractors as well, and tractor being not motor vehicle, therefore, claim of the Revenue was that different rate would apply, however, the court analysing the provisions, came to the conclusion that battery specifically falls as component part even though it has been used in a tractor and thus directed to apply the same rate.

.....
The Allahabad High Court in the case of Tudor India Limited V. State of U.P.2014 SCC Online All 11944, had also a occasion of considering sale of automotive batteries and held that battery is an essential component for the functioning of tractor and is an integral part of tractor and, therefore, the same rate was required to be applied.

The Allahabad High Court in the case of Commissioner of Sales Tax V. Banaras Battery Works 1981 U.P.T.C 974, had an occasion to consider whether battery is an accessory or a part and it held that while an accessory has been held to be an article

which is used for convenient and smooth functioning, whereas a battery cannot be said to be an accessory rather a vehicle is not complete without battery as the vehicle cannot operate without a battery, therefore, battery is a component part of motor vehicle and held that same rate is applicable.

The judgment in the case of State of Uttar Pradesh & Anr. V. Kores(India) Ltd. (supra) was relating to ribbon used in a typewriter, and the court found as finding of fact that it was an accessory and not a part of typewriter(unlike spool), though it may not be possible to use the latter without the former. The apex court also found that typewriters are being sold in market without a typewriter ribbon and, therefore, typewriter ribbon is not an essential part of typewriter so as to attract a lower rate of tax, and facts are distinguishable as in the instant case it is an integral part of RCR and cannot be separated.

Taking into consideration the aforesaid and for the reason assigned, the claim of assessee, in my view, appears to be just and proper and the rate of 4% was rightly paid by the assessee and is not required to be interfered with. The petition succeeds and the order of Tax Board dt 28.03.2012 is reversed."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय इन प्रकरणों पर पूर्णतया बाध्यकारी एवं आच्छादित है। अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत बैटरी पर 5 प्रतिशत की दर से ही कर देयता विधिसम्मत है। अतः इस बिन्दु पर सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर व ब्याज अपास्त कर अपीलीय अधिकारी के आदेश को भी निरस्त किया जाता है।

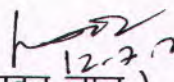
जहां तक व्यवहारी द्वारा बिक्रीत एडोप्टर/चार्जर का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय Appeal No. 11486-11487 of 2014 State of Punjab Vs Nokia India Pvt. Ltd. निर्णय तिथि 17.12.2014 का सुसंगत वर्णन निम्नानुसार है :-

"In view of the aforesaid facts, we find that the Assessing Authority, Appellate Authority and the Tribunal rightly held that the mobile/cell phone charger is an accessory to cell phone and is not a part of the cell phone. we further hold that the battery charger cannot be held to be a composite part of the cell phone but is an independent product which can be sold separately, without selling the cell phone. The High Court failed to appreciate the aforesaid fact and wrongly held that the battery charger is a part of the cell phone."

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलों को आंशिक स्वीकार किया जाता है। परन्तु अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 28 में दिनांक 06.03.2013 को संशोधन कर प्रविष्टि सं0 1 से 27 तक के आइटम की एसेसरीज को भी 5/5.5 प्रतिशत की करदेयता में रख दिये जाने से दिनांक 06.03.2013 के पश्चात बैटरी चार्जर/एडोप्टर पर कर दर संशोधित दर से लागू होगी। परन्तु दिनांक 06.03.2013 से पूर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.12.2014 (उपरोक्त) के अनुसार सामान्य कर दर रहेगी। उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार करारोपण हेतु प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य


(मदन लाल)
सदस्य